



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]  
No. 321]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2017/श्रावण 26, 1939  
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2017/SRAVANA 26, 1939

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 3 अगस्त, 2017

सं. टीएमपी/44/2017—एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963(1963 का 38) की धारा 48 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव, जोकि एमबीपीटी के एसओआर में आर एफ आई डी टैग शुल्क शामिल करने के लिए है, को निम्नलिखित आदेश द्वारा निपटाता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

केस स. टीएमपी/44/2017 — एमबीपीटी

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

- - -

आवेदक

कोरम

- (i) श्री टी एस बाला सुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(जुलाई 2017 के 21 वें दिन पारित)

यह मामला मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) द्वारा एमबीपीटी के एसओआर में आरएफआईडी टैग शुल्क शामिल करने के लिए दायर एक प्रस्ताव से संबंधित है।



2.1. एमबीपीटी ने अपना पत्र संख्या एफए/एसीसी/222/640 दिनांक 18 मई 2017 को उपरोक्त विषय पर प्रस्ताव को फाइल किया है। इसके प्रस्ताव में एमबीपीटी द्वारा बनाए गए मुख्य बिंदु निम्न संक्षेप में दिए गए हैं:

- (i). एमबीपीटी वाहन पंजीकरण मॉड्यूल के स्वचालन की प्रक्रिया में है। तदनुसार, एमबीपीटी रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी) आधारित एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का कार्यान्वयन कर रहा है, जहां बंदरगाह परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों को आरएफआईडी टैग जारी करने के लिए प्रावधान किया जाता है ताकि लम्बी दूरी तक, गेट स्वचालन के लिये आरएफआईडी पाठकों को टैग पढ़ने और वाहन को पहचानने में सक्षम बनाया जा सके।
- (ii) इस संबंध में, एमबीपीटी ने व्यापार को दिनांक 11 मार्च 2017 को एक परिपत्र, अन्य बातों के साथ जारी किया है, यह सूचित किया है कि आरएफआईडी टैग को 14 मार्च 2017 से प्रभावी प्रति वाहन 34/- प्रति प्रभार के भुगतान पर जारी किया जाएगा और यह शुरू हो गया है। [परिपत्र की एक प्रति एमबीपीटी द्वारा प्रस्तुत की गई है]। उगाही के संबंध में उपयोगकर्ताओं से कोई आपत्ति नहीं मिली थी।
- (iii) ट्रस्टी बोर्ड द्वारा दिनांक 31.03.2017 के टीआर संख्या 186 के माध्यम से अध्याय IX में, एमबीपीटी के मौजूदा स्केल में विविध शुल्क शामिल करने के लिए, निम्नलिखित प्रावधान को मंजूरी दे दी है –

. "सभी प्रकार के वाहन जैसे कार्गो वाहन, कार्गो हैंडलिंग उपकरण, कांटेक्टर 'वाहन (सामग्री), यात्री वाहन (कार आदि) को आरएफआईडी टैग शुल्क ₹.34/- प्रति वाहन लगाए जाएंगे।

आरएफआईडी टैग्स की हानि या क्षति के मामले में, आरएफआईडी टैग शुल्क @ ₹.34/- प्रति वाहन की वसूली पर ही जारी किया जाएगा।

एमबीपीटी कर्मचारियों के वाहनों को आरएफआईडी शुल्कों के उगाही से छूट दी जाएगी। "

[बोर्ड संकल्प की एक प्रति एमबीपीटी द्वारा प्रस्तुत की गई है]

3. निर्धारित सलाहकार प्रक्रिया के अनुसार, 18 मई 2017 के एमबीपीटी पत्र की एक प्रति संबंधित संबंधित प्रयोक्ताओं / उपयोगकर्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए 26 मई 2017 के पत्र के माध्यम से भेजा गया था। जब तक मामले को अंतिम रूप दिया गया तथा इस आदेश के पारित होने तक, हमें किसी भी उपयोगकर्ता / उपयोगकर्ता संगठन से कोई टिप्पणी नहीं मिली है।

4. प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच के आधार पर, हमने 13 जून 2017 के हमारे पत्र के माध्यम से एमबीपीटी से निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण मांगी है। जवाब में, एमबीपीटी ने अपने पत्र संख्या एफए/एसीसी/222/1316 दिनांक 29 जून 2017 को उत्तर दिया है। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण और उस पर एमबीपीटी की प्रतिक्रिया नीचे सारणीबद्ध है:

संख्या	हमारे द्वारा मांगी गई जानकारी/स्पष्टीकरण	एमबीपीटी के उत्तर
(i).	एमबीपीटी ने पहले ही मई 2017 में हमारे साथ एक प्रस्ताव दाखिल करने से पहले एक ट्रेड परिपत्र जारी करने के माध्यम से 14 मार्च 2017 से प्रभावी आरएफआईडी शुल्कों का अधिग्रहण शुरू कर दिया है।	20 जून 2017 को टीएएमपी द्वारा आयोजित संयुक्त सुनवाई में कारण, स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है।



	बंदरगाह के किसी भी प्रकार की उगाही की धारा 48 मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 को इस प्राधिकरण की मंजूरी की आवश्यकता है। इस संबंध में, एमबीपीटी स्थिति स्पष्ट करे।	
(ii).	एमबीपीटी उस दिनांक को भी सूचित कर सकता है, जहां से वह आरएफआईडी शुल्क के लिए मंजूरी चाहता है। यदि पोर्ट उगाही के प्रारंभ होने की तारीख से अनुमोदन प्राप्त करना चाहता है और इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम दर को मंजूरी दी जाएगी, तो अब तक एमबीपीटी द्वारा एकत्र की गई दर से अलग है, एमबीपीटी इस बात का संकेत देने के लिए कि वह विभेदक राशि एकत्र की गई, एमबीपीटी, उसके द्वारासे एकत्रित राशि के लिए परिकल्पित उपचार का संकेत करे।	यह 14 मार्च 2017 से लागू आरएफआईडी शुल्क के उगाही की अनुमति के लिए संयुक्त सुनवाई के दौरान टीएएमपी को प्रस्तुत किया गया था।
(iii).	एमबीपीटी ने ₹.28/- प्रति वाहन की आधार दर और वैधानिक करों पर विचार करने के बाद, मूल्य वर्धित कर (वैट) और चुंगी शुल्क के आधार पर आरएफआईडी टैग शुल्क के प्रति ₹.34/- प्रति वाहन की दर का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में, यह कहना है कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित शुल्क किसी भी करों और वैधानिक कर्तव्यों से अनन्य है। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित टैरिफ पर लागू दर पर बंदरगाह द्वारा कर और वैधानिक शुल्क लगाए जाने हैं। इस प्रकार, एमबीपीटी ध्यान दें कि यह प्राधिकरण केवल आधार आरएफआईडी टैग शुल्क के लिए मंजूरी देगा।	एमबीपीटी आरएफआईडी आधारित एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें डॉक परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों को आरएफआईडी टैग जारी करने के लिए प्रावधान किया जाता है ताकि लंबी दूरी तक पढ़ने वाले आरएफआईडी रीडर को टैग पढ़ने और गेट ऑटोमेशन के लिए वाहन की पहचान कर सकें। मामले को संयुक्त रूप से आरएफआईडी टैग शुल्क के प्रति ₹.34/- प्रति वाहन की दर के लिए संयुक्त सुनवाई के दौरान पेश किया गया था, जिसमें मूल्य जोड़ा गया कर और चुंगी शुल्क या जीएसटी शामिल हैं।
(iv).	₹.28/- प्रति वाहन के प्रस्तावित आधार आरएफआईडी टैग शुल्क के समर्थन में कार्य।	मेसर्स को प्रतिपूर्ति के लिए आरएफआईडी टैग के प्रभार लागत पर लागत के आधार पर माना जाता है। विप्रो को प्रतिपूर्ति करनी है, जो गेट ऑटोमेशन को लागू कर रहे हैं, जिसके लिए मेसर्स विप्रो लिमिटेड को अनुबंध दिया गया है। अन्य उपयोगकर्ताओं से शुल्क नहीं लिया जाता है।
(v).	उपर्युक्त (iv) पर कामकाज में माने जाने वाले कॉस्ट एलिमेंट के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य	सफल बोलीदाता मेसर्स विप्रो लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत मूल्य बोली की प्रतिलिपि उपलब्ध है। संबंधित लागत आइटम हाइलाइट किया गया है। (कीमत की बोली से, यह देखा जाता है कि आरएफआईडी टैग के लिए ₹.28/- की राशि निर्धारित की गई है और 12.5% पर वैट का



		एक घटक और <b>5.5%</b> पर चुंगी शुल्क का संकेत दिया गया है।
(vi).	प्रस्तावित आरएफआईडी शुल्क के लागू होने के कारण प्रति वर्ष एमबीपीटी के लिए, कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।	प्रति वर्ष एमबीपीटी के लिए कोई अतिरिक्त राजस्व अर्जित नहीं होगा, क्योंकि आरएफआईडी शुल्क के खिलाफ कोई प्रशासनिक लागत नहीं माना गया है।

5. संदर्भ में मामले की संयुक्त सुनवाई 20 जून 2017 को मुंबई में इस प्राधिकरण के कार्यालय में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई पर, एमबीपीटी ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं।

6. इस मामले में परामर्श से संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। एमबीपीटी द्वारा बनाए गए तर्कों का अंश अलग-अलग पार्टियों को अलग से भेजा जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

7. मामले की प्रसंस्करण के दौरान एकत्र की गई सूचना की संपूर्णता के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति उभरती है:

- (i) 'व्यापार करने में आसानी' की सरकार की पहल के रूप में, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी) आधारित एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को लागू किया है, जहां एक बार आरएफआईडी टैग सभी कार्गो वाहनों और यात्री वाहनों को गोदी परिसर में प्रवेश करने के लिए जारी किए जाएंगे, ताकि लंबे समय तक आरएफआईडी पाठक टैग को पढ़ने और गेट ऑटोमेशन के लिए वाहन की पहचान कर सके। प्रस्तावित आरएफआईडी प्रोजेक्ट को सूचित किया जाता है कि बंदरगाह आवागमन को सुगम बनाये ताकि, अतिरिक्त रहने और कार्गो विवरण आदि के पूरे ट्रैक के साथ डॉक में प्रवेश करने वाली वाहन की निगरानी हो सके। इस प्रकार, बंदरगाह का प्रस्ताव आरएफआईडी शुल्क को उसके स्केल रेट में शामिल करना है।
- (ii) इस संबंध में, एमबीपीटी ने ₹34/- प्रति आरएफआईडी टैग की दर प्रस्तावित की है। उक्त दर आरएफआईडी टैग की लागत पूरी तरह से दर्ज की गई है, जो एमबीपीटी द्वारा लगाई जाएगी और पोर्ट में गेट ऑटोमेशन सिस्टम को कार्यान्वित करने के लिए एमबीपीटी द्वारा निगमित ठेकेदार को पारित किया जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ आरएफआईडी टैग के एकीकरण से संबंधित लागत और अन्य प्रशासनिक खर्च पोर्ट द्वारा अपने संसाधनों से पूरा करने का प्रस्ताव है।
- (iii) एमबीपीटी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से, यह देखा जाता है कि प्रत्येक आरएफआईडी टैग की आधार लागत ₹.28/- है और चुंगी शुल्क 5.5% और 12.5% वैट पर शामिल होने के बाद आरएफआईडी टैग की लागत को एमबीपीटी द्वारा ₹.34 / - प्रति टैग पर जमा दिया गया है। आम तौर पर, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित शुल्क किसी भी कर और सांविधिक कर्तव्यों से अनन्य है। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित टैरिफ, लागू दर पर बंदरगाह द्वारा कर और वैधानिक शुल्क लगाए जाने हैं। हालांकि, इस मामले के संदर्भ में, एमबीपीटी ने पुष्टि की है कि प्रस्तावित आरएफआईडी शुल्कों में करों का घटक कोई परिवर्तन नहीं होगा, भले ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के अनुसार कर ढांचे में कोई परिवर्तन आए।



- (iv) बंदरगाह से ऊपर दी गयी की पुष्टि के मद्देनजर और चूंकि बंदरगाह के प्रस्ताव के पास अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मंजूरी है और किसी उपयोगकर्ता / उपयोगकर्ता संगठनों को कोई आपत्ति नहीं है, यह प्राधिकरण आरएफआईडी शुल्क को ₹.34 / - प्रति शेयर को मंजूरी देना चाहता है, जैसा कि पोर्ट द्वारा प्रस्तावित है।
- (v) किसी भी नए टैरिफ की उगाही पोर्ट के लिए अतिरिक्त राजस्व का परिणाम होगा, जो मई 2016 में एमबीपीटी के टैरिफ के सामान्य संशोधन के दौरान अनुमानित नहीं हो सकता था। हालांकि, आरएफआईडी टैग की लागत एमबीपीटी द्वारा लगाई गई है और और ठेकेदार को पारित कर दिया, इन शुल्कों के लागू होने के कारण एमबीपीटी के लिए अर्जित किसी भी अतिरिक्त आय का सवाल उठता ही नहीं है।
- (vi). पोर्ट द्वारा किसी भी शुल्क की लेवी जो कि प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 48 में शामिल है, वो इस प्राधिकरण की मंजूरी की आवश्यकता रखता है। एमबीपीटी द्वारा दायर किए गए प्रस्ताव से, यह देखा जाता है कि एमबीपीटी ने मई 2017 में अपने प्रस्ताव को दाखिल करने से पहले ही एक व्यापार परिपत्र जारी करने के माध्यम से 14 मार्च 2017 से आरएफआईडी शुल्कों का प्रयोग शुरू कर दिया है। इस प्रकार, एमबीपीटी ने 14 मार्च 2017 से, एक उचित स्थिति पेश करते हुए प्राधिकरण को प्रस्तावित संशोधन के लिए मंजूरी मांगी है। प्राधिकरण के सामने प्रत्यावर्तित स्थिति पेश करने के बजाय टैरिफ के संशोधन के लिए अग्रिम कार्रवाई करने या किसी नए दरों की शुरूआत करने के लिए पोर्ट की अपेक्षा करने के लिए अनुचित नहीं है। कार्यशील दिशानिर्देश नई सुविधा या नई सेवा के उपयोग के लिए दर के अधिसूचना के प्रस्ताव को दाखिल करने के लिए और एक साथ एडहॉक तरीके से प्रस्तावित दरों की उगाही के लिए प्रदान करते हैं।
- (vii). इस प्राधिकरण के आदेश आम तौर पर राज-पत्र अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद संभावित रूप से प्रभाव में आते हैं, जब तक अन्यथा अलग-अलग व्यवस्था संबंधित टैरिफ ऑर्डर में नहीं दी जाती है। असाधारण मामलों में, रिकॉर्ड किए जाने के कारण पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाता है। मामले में संदर्भ में, 14 मार्च 2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव के संबंध में उपयोगकर्ताओं से कोई आपत्ति नहीं है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह प्राधिकरण 14 मार्च 2017 से प्रभावी आरएफआईडी शुल्क की पूर्वव्यापी उगाही के लिए मंजूरी दे रहा है। हालांकि, एमबीपीटी को सलाह दी जाती है कि व्यापारियों को, वे परिपत्रों के द्वारा दरों और शर्तों के स्तर में बदलाव के बारे में, इस प्राधिकरण के अनुमोदन से पहले सूचित करते रहना जारी ना रखे।

8.1 इसके परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों के लिए, और सामूहिक आवेदन के आधार पर, इस प्राधिकरण ने अध्याय IX - एमबीपीटी के मौजूदा स्केल में विविध शुल्क, के तहत निम्नलिखित धारा 9.6 को शामिल करने के लिए अनुमोदन को स्वीकार किया।

#### **"9.6 आरएफआईडी टैग के लिए शुल्क**

माल वाहनों, कार्गो हैंडलिंग उपकरण, ठेकेदारों के वाहन (सामग्री), यात्री वाहन (कार, आदि) जैसे सभी प्रकार के वाहनों को @ ₹.34/- प्रति वाहन आरएफआईडी टैग शुल्क लगाया जाएगा।



आरएफआईडी टैग्स की हानि या क्षति के मामले में, आरएफआईडी टैग शुल्क @ ₹.34/- प्रति वाहन की वसूली पर ही जारी किया जाएगा।

एमबीपीटी के कर्मचारियों के वाहनों को आरएफआईडी शुल्क के लिए छूट दी जाएगी।”

8.2 एमबीपीटी को सलाह दी जाती है कि इसके दर के स्केल में उपर्युक्त प्रावधान को उचित रूप से शामिल करें।

8.3. यह शुल्क 14 मार्च 2017 से लागू हुआ माना जाता है और इसकी वैधता एमबीपीटी के मौजूदा पैमाने के साथ-साथ ही समाप्त होगी जो की 31 मार्च 2019 तक की है।

टी. एस. वालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./186/17]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd August, 2017

**No. TAMP/44/2017-MBPT.**—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for incorporation of RFID Tags charges in the SOR of MBPT, as in the Order appended hereto.

### Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/44/2017-MBPT

The Mumbai Port Trust

---

Applicant

### QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

### ORDER

(Passed on this 21<sup>st</sup> day of July 2017)

This case relates to a proposal filed by the Mumbai Port Trust (MBPT) for incorporation of RFID Tags charges in the SOR of MBPT.

2.1. The MBPT *vide* its letter No. FA/ACC/222/640 dated 18 May 2017 has filed the proposal on the subject cited above. The main points made by the MBPT in its proposal are summarized below:

- (i). The MBPT is in the process of automation of vehicle registration module. Accordingly, the MBPT is implementing Radio Frequency Identification (RFID) based Access Control System, where provision is made to issue RFID tag to all the vehicles entering the dock premises to enable the long range RFID readers to read the tag and identify the vehicle for the gate automation.
- (ii). In this connection, the MBPT has issued a circular dated 11 March 2017 to the Trade, *inter alia*, informing that RFID tag will be issued on payment of charges @ ₹34/- per vehicle with effect from 14 March 2017 and the same has commenced. [A copy of the circular is furnished by MBPT]. No objection was received from users with regard to the levy.



- (iii). The Board of Trustees *vide* TR No. 186 dated 31.03.2017 has accorded sanction to include the following provision at Chapter IX - Miscellaneous Charges in the existing Scale of Rates of MBPT.

“All types of vehicles like cargo vehicles, cargo handling equipment, contractors’ vehicles (material), passenger vehicles (car, etc.) will be levied RFID tag charges @ ₹34/- per vehicle.

In case of loss or damage of RFID tags, the same shall be issued on recovery of RFID Tags charges @ ₹34/- per vehicle.

The vehicles of MBPT employees will be exempted from levy of RFID charges”.

[A copy of the Board Resolution is furnished by MBPT].

3. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the MBPT letter dated 18 May 2017 was forwarded to the concerned users/ user organizations *vide* our letter dated 26 May 2017 seeking their comments. We have not received any comments from any of the users / user organisations, till this order is passed.

4. Based on a preliminary scrutiny of the proposal, we have *vide* our letter dated 13 June 2017 sought the following additional information / clarification from the MBPT. In response, the MBPT *vide* its letter No. FA/ACC/222/1316 dated 29 June 2017 has responded. The information / clarification sought by us and the response of MBPT thereon are tabulated below:

No.	Information/ clarification sought by us	Response of MBPT
(i).	The MBPT has already commenced levy of RFID charges with effect from 14 March 2017 by way of issue of a Trade Circular much prior to even filing a proposal with us in May 2017. Levy of any charges by the Port which are covered by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963, requires approval of this Authority. In this regard, the MBPT to clarify the position.	The reasons have been amply clarified in the joint hearing held by TAMP on 20 June 2017.
(ii).	The MBPT may also intimate the date from which it seeks approval for the RFID charges. If the port wishes to seek approval from the date of commencement of levy and in the event the final rate to be approved by this Authority is different from the rate collected by MBPT till date, the MBPT to indicate the treatment envisaged by it for the differential amount so collected.	It was further submitted to TAMP during the joint hearing to allow levy of RFID charges with effect from 14 March 2017.
(iii).	The MBPT has proposed a rate of ₹34/- per vehicle towards RFID Tag charges by considering a base rate of ₹28/- per vehicle and after considering statutory taxes viz., Value Added Tax (VAT) and Octroi charges. In this regard, it is to state that the tariff approved by this Authority is exclusive of any taxes and statutory duties. The taxes and statutory duties are to be levied by the Port at the applicable rates on the tariff so approved by this Authority. Thus, the MBPT to note that this Authority would grant approval only for the base RFID Tag charges.	MBPT is implementing RFID based Access Control System wherein provision is made to issue RFID tag to all the vehicles entering the Dock premises to enable the long range RFID readers to read the tag and identify the vehicle for the gate automation. The matter was represented during the joint hearing for a rate of ₹.34/- per vehicle towards RFID tag charges, which include the Value Added Tax and Octroi charges or GST as the case may be.
(iv).	Workings in support of the proposed base RFID Tag charges of ₹28/- per vehicle.	The charge of RFID tag have been considered on cost to cost basis to be reimbursed to M/s. Wipro who are implementing the Gate Automation for which contract has been awarded to M/s Wipro Ltd. No other charges are levied from the users.
(v).	Documentary evidence in support of the cost elements considered in the workings at (iv) above.	Copy of price bid submitted by successful bidder M/s. Wipro Ltd. Is furnished. The relevant cost item is highlighted. (From the price bid, it is seen that an amount of ₹28/- has been prescribed for RFID tags and a component of VAT at 12.5% and Octroi charges at 5.5% has been indicated.



(vi).	Additional revenue that would accrue to MBPT per annum on account of the levy of the proposed RFID charges.	No additional revenue will accrue to MBPT per annum, as no administrative cost has been considered against the RFID charges.
-------	---	--

5. A joint hearing on the case in reference was held on 20 June 2017 at the office of this Authority in Mumbai. At the joint hearing, the MBPT has made its submissions.

6. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made by the MBPT will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

7. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

- (i) As part of Government's initiative of 'Ease of doing business', the Mumbai Port Trust (MBPT) has implemented the Radio Frequency Identification (RFID) based Access Control System, where one time RFID tags will be issued to all the cargo vehicles and passenger vehicles entering the dock premises to enable the long range RFID readers to read the tag and identify the vehicle for the gate automation. The proposed RFID project is reported to facilitate the port to monitor the vehicle entering the docks with complete track of movement, overstayal and cargo details, etc. Thus, the proposal of the port is to incorporate the RFID charges in its Scale of Rates.
- (ii). In this connection, the MBPT has proposed a rate of ₹ 34/- per RFID tag. The said rate is reported to be purely the cost of RFID tags, which will be levied by the MBPT and passed on to the Contractor engaged by the MBPT to implement the Gate Automation system at the Port. The cost relating to integration of RFID tags with Hardware and Software and the other administrative expenses is proposed to be met by the Port from its own resources.
- (iii). From the documents furnished by the MBPT, it is seen that the base cost for each of the RFID Tag is ₹ 28/- and with inclusion of Octroi charges at 5.5% and VAT at 12.5%, the cost of RFID tag has been rounded off by MBPT at ₹ 34/- per tag. Generally, the tariff approved by this Authority is exclusive of any taxes and statutory duties. The taxes and statutory duties are to be levied by the Port at the applicable rates on the tariff so approved by this Authority. However, in the case in reference, the MBPT has confirmed that the component of taxes in the proposed RFID charges will not undergo any change even if there is any change in the tax structure as per the Goods and Service Tax (GST).
- (iv). In view of the above confirmation from the port and since the proposal of the port has the approval of its Board of Trustees and there being no objections from any of the users/ user organisations, this Authority is inclined to approve the RFID charges at ₹ 34/- per tag, as proposed by the Port.
- (v). Levy of any new tariff would result in additional revenue to the port, which may not have been anticipated during the general revision of tariff of MBPT in June 2016. However, since the cost of RFID tags is reported to be levied by the MBPT and passed on to the Contractor, the question of any additional income accruing to MBPT on account of levy of these charges does not arise.
- (vi). Levy of any charges by the Port which are covered by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963, requires approval of this Authority. From the proposal filed by the MBPT, it is seen that the MBPT has already commenced levy of RFID charges with effect from 14 March 2017 by way of issue of a Trade Circular much prior to filing its proposal in May 2017. Thus, the MBPT has sought approval to the proposed amendment with effect from 14 March 2017 presenting a fait accompli situation to this Authority. It is not unreasonable to expect a port to take advance action for modification of tariff or introduction of any new rates instead of presenting fait accompli situation before this Authority. The working guidelines provide for filing of the proposal for notification of rate for use of a new facility or a new service and levy of proposed rates on adhoc manner simultaneously.
- (vii). Orders of this Authority generally come into effect prospectively after expiry of 30 days from the date of Gazette Notification unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the respective tariff Orders. In exceptional cases, retrospective effect is given for reason to be recorded. In the case in reference, there is no objection from the users with regard to retrospective effect from 14 March 2017. In view of this position, this Authority is inclined to grant approval for retrospective levy of RFID charges with effect from 14 March 2017. However, the MBPT is advised to refrain from



issuing Circulars to Trade intimating about change in the Scale of Rates and conditions, prior to this Authority according approval to the proposed changes.

8.1 In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority accords approval for incorporation of following new Section 9.6 under Chapter IX - Miscellaneous Charges in the existing Scale of Rates of MBPT.

**“9.6 Charges for Issue of RFID Tags**

All types of vehicles like cargo vehicles, cargo handling equipment, contractors’ vehicles (material), passenger vehicles (car, etc.) will be levied RFID tag charges @ ₹34/- per vehicle.

In case of loss or damage of RFID tags, the same shall be issued on recovery of RFID Tags charges @ ₹34/- per vehicle.

The vehicles of MBPT employees will be exempted from levy of RFID charges.”

8.2 The MBPT is advised to suitably incorporate the above provision in its Scale of Rates.

8.3. The said charge is deemed to have come into effect from 14 March 2017 and its validity shall remain co-terminus to the validity of the existing Scale of Rates of MBPT upto 31 March 2019.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./186/17]